



दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ೫೦ನೇ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | ಬೆಂಗಳೂರು और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

5 बापू एक व्यक्ति नहीं, सोच हैं : राहुल

6 अंतरिक्ष में जल्लू दिखेगा सुपरमून का दिलचस्प नजारा

7 'कोहरा 2' से मोना सिंह ने लिया जिंदगी का सबक



फ़र्स्ट टेक

केआईए पर 2.77 करोड़ रुपए मूल्य का गांजा जल्लू, एक गिरफ्तार

बेंगलूरु। बेंगलूरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (केआईए) पर शुक्रवार को बैंकोंक से आए एक यात्री से 2.77 करोड़ रुपये मूल्य का गांजा बरामद किया गया। बाद में उसे तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, आरोपी को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, आरोपी की पहचान अभी उजागर नहीं की गई है। सीमा शुल्क विभाग ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, अधिकारियों ने बैंकोंक से आए एक यात्री को रोका और उसके सामान में छिपाकर रखा गया 7.92 किलोग्राम गांजा बरामद किया। अधिकारियों के अनुसार जब्त किए गए गांजे की कीमत 2.77 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है।

अमेरिका भारत को तीन प्राचीन कांस्य मूर्तियां लौटाएगा

न्यूयॉर्क/बापा। अमेरिका भारत को तीन प्राचीन कांस्य मूर्तियां लौटाएगा जिन्हें देश के मंदिरों से अवैध रूप से हटा दिया गया था। वाशिंगटन डीसी स्थित स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट ने कहा कि तीन मूर्तियां भारत सरकार को वापस की जाएंगी। गहन जांच के बाद इन मूर्तियों के स्त्रोत का पता लगाया गया और रिपोर्ट में यह कहा गया कि इन मूर्तियों को मंदिरों से अवैध रूप से हटाया गया था। संग्रहालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत सरकार ने मूर्तियों में से एक को दीर्घकालिक ऋण पर देने पर सहमति व्यक्त की है। इस तरह की व्यवस्था के तहत संग्रहालय को वस्तु की उत्पत्ति, उन्हें हटाए जाने और वापसी की पूरी कहानी को सार्वजनिक रूप से साझा करने की अनुमति मिल जाएगी।

इजराइल गाजा की रफा सीमा चौकी को फिर से खोलेगा

यरूशलेम/एपी। इजराइल ने शुक्रवार को कहा कि वह गाजा की मिस्र के साथ लगी रफा सीमा चौकी को रविवार को फिर से खोल देगा। करीब दो साल बाद इस चौकी को फिर से खोले जाने से फलस्तीनियों को क्षेत्र में प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति मिलेगी। गाजा को सहायता पहुंचाने के समन्वय के लिए जिम्मेदार इजराइली सैन्य इकाई सीओजीएटी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि केवल सीमित आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। रफा सीमा चौकी को खोला जाना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा युद्धविराम योजना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

31-01-2026 | 31-01-2026
सूर्योदय 6:20 बजे | सूर्यास्त 6:45 बजे

BSE 82,269.78 (-296.59)
NSE 25,320.65 (-98.25)

सोना 17,422 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम
चांदी 320,000 रु. प्रति किलो

मिशान मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com



केलाशा मण्डेला, मो. 9828233434

झूठों की भरमार

कड़ी सजा का प्रावधान हो, यदि फर्जी हो एफआइआर। झूठा होवे यदि गवाह तो, हो दोषी सम भागीदार। मगर सबूतों पर आश्रित हैं, सारे कानूनी हथियार। कैसे करें फेसला सच पर, जब हो झूठों की भरमार।



राहुल गांधी ने पूर्वोत्तर का अपमान किया : शाह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

■ जो लोग अवैध रूप से भारत आए हैं, उनकी पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाएगा।

डिब्रूगढ़/धेमाजी/बापा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के अभियान को तेज करते हुए कांग्रेस, विशेष रूप से राहुल गांधी पर पूर्वोत्तर का अपमान करने, चुनावी राजनीति के लिए घुसपैठ को बढ़ावा देने और क्षेत्र के विकास की अनदेखी करने का शुक्रवार को आरोप लगाया। शाह ने राज्य के अपने दौरे के दौरान 1,715 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने विभिन्न मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए

मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की प्रशंसा की और लोगों से लगातार तीसरी बार भाजपा को सत्ता में लाने की अपील की। शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित 'एट होम' कार्यक्रम में भेद किया गया 'गमोसा' पहनने से इनकार कर पूर्वोत्तर का अपमान किया है। गृह मंत्री ने डिब्रूगढ़ में 'खानिकार परेड ग्राउंड' में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि विदेश से आए

अतिथियों समेत सभी गणमान्य लोगों ने सम्मान के प्रतीक के तौर पर 'गमोसा' पहना था, लेकिन राहुल 'एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने इसे पहनने से इनकार कर दिया।' उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में है, वह पूर्वोत्तर की संस्कृति का कोई अपमान नहीं होने देगी।' शाह ने कांग्रेस पर घुसपैठ को 'वोट बैंक की राजनीति के लिए हथियार' की तरह इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने किया सवाल

क्या मनरेगा के बाद आरटीआई को खत्म करना चाहती है सरकार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



नई दिल्ली/बापा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आर्थिक समीक्षा में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम का फिर से अध्ययन करने की पैरवी किए जाने का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा कि क्या सरकार मनरेगा के बाद अब इस कानून को खत्म करना चाहती है? संसद में बृहस्पतिवार को प्रस्तुत वर्ष 2025-26 की आर्थिक समीक्षा में लगभग दो दशक पुराने आरटीआई कानून का फिर से अध्ययन करने की

वकालत की गई है, ताकि गोपनीय रिपोर्ट और मसौदों को सार्वजनिक किए जाने से छूट प्राप्त हो। आर्थिक समीक्षा में यह भी कहा गया कि आरटीआई अधिनियम 2005 का मकसद कभी भी इसे व्यर्थ की जिज्ञासा का जरिया बनाने का नहीं था, न ही इसका मकसद बाहर से बैठकर सरकार के हर छोटे-छोटे काम में दखल देना या उसे नियंत्रित करना था।

खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'आर्थिक समीक्षा ने सूचना का अधिकार अधिनियम की फिर से अध्ययन करने की पैरवी की है। यह सूचना को रोकने के लिए संभावित मंत्री स्तरीय वीडियो का सुझाव भी देती है और यह देखने की बात करती है कि क्या नौकरशाहों की सार्वजनिक सेवा से जुड़े रिकॉर्ड, तबादले और स्टाफ रिपोर्ट्स को सार्वजनिक निगरानी से बाहर रखा जा सकता है।' उन्होंने कहा, 'मोदी सरकार ने व्यवस्थित रूप से आरटीआई अधिनियम को कमजोर किया है। 2025 तक 26,000 से ज़्यादा मामले लंबित हैं।

धोखाधड़ी की शिकायतों के बाद

सरकार ने विंगो ऐप को 'ब्लॉक' किया

नई दिल्ली/बापा। सरकार ने विंगो ऐप को कथित तौर पर उपयोगकर्ताओं के फोन से फर्जी एसएमएस भेजने और उनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर संदेश आधारित साइबर अपराध करने के आरोप में 'ब्लॉक' कर दिया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय और उसकी साइबर अपराध रोधी एजेंसी, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने एंज़ाईड ऐप के खिलाफ कई शिकायतें मिलने के बाद यह कार्रवाई की। एजेंसी ने कहा कि ऐप उपयोगकर्ता अनजाने में साइबर अपराधियों द्वारा चलाए जा रहे एसएमएस धोखाधड़ी नेटवर्क में भागीदार बन रहे थे। शिकायतों के बाद, सरकार ने ऐप के नियंत्रण केंद्र को 'ब्लॉक' कर दिया। आई4सी ने बताया कि 1.53 लाख उपयोगकर्ताओं वाले चार टेलीग्राम चैनल और ऐप का प्रचार करने वाले 50 से अधिक यूट्यूब वीडियो भी ब्लॉक कर दिए गए।

फलस्तीन की विदेश मंत्री वारसेन अगाबेकियन शाहीन ने कहा

ट्रंप के 'पुनर्निर्माण' विचार का स्वागत, बशर्ते गाजावासियों को लाभ मिले

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/बापा। फलस्तीन की विदेश मंत्री वारसेन अगाबेकियन शाहीन ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा के पट्टी के 'पुनर्निर्माण' के विचार से फलस्तीन को शायद कोई आपत्ति न हो, लेकिन ऐसा केवल तभी होगा जब ऐसी योजना का लाभ फलस्तीनियों को मिले, न कि उसे उन पर थोपा जाए। शाहीन ने 'पीटीआई वीडियो' को दिए एक साक्षात्कार में यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के 'शांति बोर्ड' में भारत की भागीदारी मददगार साबित हो सकती है।



ट्रंप के गाजा पट्टी को 'पश्चिम एशिया का लोकप्रिय स्थान' बनाने के विचार से जुड़े वैश्विक ध्यान केंद्रित होने और ट्रंप द्वारा प्रस्तावित अमेरिकी नेतृत्व वाले 'शांति बोर्ड' के बीच आई हैं। शांति लाने के ऐसे किसी भी प्रयास का स्वागत करते हुए, शाहीन ने इस बात पर जोर दिया कि गाजा के पुनर्निर्माण के विचार को फलस्तीनी राजनीतिक अधिकारों से अलग नहीं देखा जा सकता।

कर्नाटक में बसों और बस स्टैंड पर तंबाकू के विज्ञापनों पर लगा प्रतिबंध

बेंगलूरु/बापा। कर्नाटक के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने शुक्रवार को अधिकारियों को राज्य के चार परिवहन निगमों की बसों और बस स्टैंड पर तंबाकू उत्पादों के सेवन को बढ़ावा देने वाले सभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर रोक लगाने के निर्देश दिए। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी), बेंगलूरु महानगर परिवहन निगम (बीएमटीसी), उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (एनडब्ल्यूकेआरटीसी) और कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (केकेआरटीसी) के प्रबंध निदेशकों को जारी एक पत्र में परिवहन मंत्री ने निर्देश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया। रेड्डी ने कहा, 'जनहित में, मैं निर्देशित करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से, परिवहन निगमों की बसों या बस स्टैंड पर तंबाकू उत्पादों के सेवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने वाले कोई भी विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे।' उन्होंने निर्देश दिया कि अगर इस तरह के विज्ञापन पहले से ही बसों या बस स्टैंड पर प्रदर्शित हैं, तो उन्हें हटाने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए और निर्धारित अवधि के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

सड़क सुरक्षा



शुक्रवार को हावेरी जिले की ट्रैफिक पुलिस ने हावेरी में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लोगों को यातायात नियमों और सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक किया गया।

गोडसे के वारिसों को उचित सबक सिखाया जाएगा : स्टालिन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



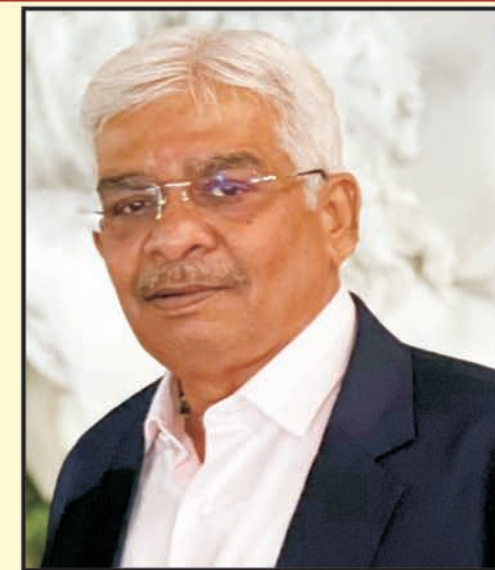
चेन्नई/बापा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी की स्मृति को मिटाने और राष्ट्र को नष्ट करने की मंशा रखने वाले नाथूराम गोडसे के वारिसों को करारा सबक सिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, आइए

धार्मिक कट्टरता का नाश करें! आइए महात्मा गांधी का सम्मान करें! विश्व को शांति के मार्ग की शक्ति का प्रदर्शन कर और एकता की भावना को बढ़ावा देकर, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें गोडसे ने गोलियों से भूना था, प्रत्येक भारतीय के हृदय में अमर रहेंगे!

हम महात्मा गांधी की स्मृति को मिटाने व राष्ट्र को नष्ट करने की मंशा रखने वाले गोडसे के वारिसों को करारा सबक सिखाएंगे और हम उस भूमि की रक्षा करेंगे, जहां गांधीजी का जन्म हुआ था।

दुःखद निधन / अंतिम यात्रा

जन्म
10.05.1958



स्वर्गवास
30.01.2026

श्री अमृतराज तलेसरा

(सुपुत्र स्व. श्रीमती मूरीबाई - स्व. श्री केसरीमलजी तलेसरा)

सादड़ी-राणकपुर / बेंगलोर

अत्यंत दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे भाई/पिताजी श्री अमृतराज तलेसरा का निधन दिनांक 30.01.2026 शुक्रवार को प्रातः 10.15 बजे बेंगलोर में हो गया है। विधि के विधान के आगे हम सभी नतमस्तक हैं।

अन्तिम यात्रा : आज दिनांक 31.01.2026 , शनिवार प्रातः 11.00 बजे

निवास स्थान से विल्सन गॉर्डन शवदाह गृह प्रस्थान होगी।

निवास स्थान: Akshay Ayush Talesara

Flat No.613, Ranka Park Apartments, No.4-5-6, Near Richmond Circle, Lalbagh Road, Bangalore-560027

M : Abhishek 9845004841, Ashish 9844057570

शोकाकुल

तिलकराज, बाबूलाल, ललितकुमार, विजयराम, कांतिलाल, अभिषेक, आशीष , अक्षय, अंकित, अधिन, आयुष, अनुज, आदित्य, सिद्धांत, कुशान, वीरान्ध, जय, खिवांश एवं समस्त तलेसरा परिवार (सादड़ी-राणकपुर), बेंगलोर

• Vijay Textiles

• Vijay Stones And Marbles

• Faarsh

• Vijay Bros.

BANGALORE

ससुराल पक्ष : स्व. खीमराजजी हंसराजजी के सुपुत्र स्व. बाबूलालजी, छगनलालजी, अमृतलालजी, स्व. ज्ञानचन्द्रजी, अशोकजी, श्रेणिकजी, राजेन्द्र, श्रीपाल, पारस, अमित, अभिषेक, विवेक, अंकित, प्रतीक, अमन एवं समस्त बाफना परिवार सादड़ी-राणकपुर / इरोड

कृपया शॉल-माला न लावें



अंडमान स्थित श्री विजय पुरम हवाई अड्डे को अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

श्री विजय पुरम/भाषा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित और सागरकर अंतरराष्ट्रीय (वीएसआई) हवाई अड्डे को 50 लाख से कम यात्रियों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाली अधिकांश सुविधाएं 50 लाख से कम की श्रेणी में आती हैं। वीएसआई हवाई अड्डे के निदेशक मुनीर मदामपत ने कहा, “यह एक गौरवपूर्ण क्षण है। इसे संभव बनाने के लिए मैं अपनी टीम को बधाई देना चाहता हूं।” उन्होंने कहा, “यह वैश्विक मान्यता इस

अगले वित्त वर्ष का वृद्धि अनुमान न तो रुढ़िवादी, न ही अधिक आशावादी : सीईए नागेश्वरन



नई दिल्ली/भाषा। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने शुक्रवार को कहा कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 में अगले वित्त वर्ष के लिए 6.87.2 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान न तो बहुत रुढ़िवादी है और न ही अत्यधिक आशावादी है। उन्होंने कहा कि इस दर से भी बढ़ने पर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने की स्थिति में रहेगा। हालांकि, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष के लिए जारी 7.4 प्रतिशत के पहले अग्रिम अनुमान से थोड़ी कम होगी। इसके विपरीत, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026-27 में 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है जबकि विश्व बैंक ने 6.5 प्रतिशत और एशियाई विकास बैंक ने 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर का

मासिक धर्म स्वास्थ्य जीवन के अधिकार का हिस्सा : सुप्रीम कोर्ट



दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मासिक धर्म स्वास्थ्य को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का अभिन्न हिस्सा घोषित किया है। अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे देश के सभी स्कूलों में छात्राओं को नि:शुल्क, मानक अनुरूप और जैविक रूप से अपघटनीय सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएं तथा लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग, कार्यात्मक शौचालय सुनिश्चित करें। यह आदेश न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने दिया। अदालत ने कहा कि मासिक धर्म से जुड़ी स्वच्छता सुविधाओं की कमी छात्राओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और गरिमा को प्रभावित करती है और यह लैंगिक समानता के अधिकार के भी विरुद्ध है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये निर्देश सरकारी, सहायता प्राप्त

लगातार नौवीं बार बजट पेश कर नया कीर्तिमान स्थापित करेंगी सीतारमण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी एक फरवरी को लगातार नौवां बजट पेश कर देश के संसदीय इतिहास में एक नया रिकॉर्ड दर्ज करेंगी। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में पेश होने वाले इस बजट से सुधारवादी कदमों के जरिये विकास को गति मिलने की काफी उम्मीदें हैं।

इस उपलब्धि के साथ ही सीतारमण पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के 10 बजट के कुल रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच जाएंगी। देसाई ने 1959-1964 के बीच छह और 1967-1969 के बीच चार बजट पेश किए थे। हालांकि, लगातार बजट पेश करने के मामले में सीतारमण सबसे आगे रहेंगी। उन्होंने पूर्व वित्त मंत्रियों पी पी चिंदंबरम (9 बजट) और प्रणब मुखर्जी (8 बजट) को भी पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने अलग-अलग कार्यकालों में ये आंकड़े छुए थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में



सीतारमण अब तक फरवरी, 2024 के अंतरिम बजट सहित लगातार आठ बजट पेश कर चुकी हैं। स्वतंत्र भारत के बजट इतिहास से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं:

पहला बजट: देश का पहला आम बजट 26

सरकार ‘सभी के लिए न्याय’ सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध: यूजीसी नियम विवाद पर भाजपा



दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भाजपा ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के विवादास्पद समानता नियमों पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि वह किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। पार्टी के राजस्वसभा सदस्य और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में इस नियम के बारे में पूछे जाने पर कहा कि सरकार “सभी के लिए न्याय” सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है।

उच्चतम न्यायालय ने जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी द्वारा पारित हालिया समानता विनियमों पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। न्यायालय ने कहा कि डॉ.वा “प्रथम दृष्टया अस्पष्ट” है, तथा इसके “बहुत व्यापक परिणाम हो सकते हैं” और अंततः यह समाज को “खतरनाक प्रभाव” के साथ विभाजित कर सकता है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बाबाजी की पीठ ने टिप्पणी की कि विनियमों में “कुछ अस्पष्टताएं” हैं और “उनके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।” शीर्ष अदालत ने कहा कि विनियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं। इसने विचार के लिए ऐसे चार प्रश्न निर्धारित किए। इस मुद्दे पर भाजपा का दृष्टिकोण पूछे जाने पर त्रिवेदी ने कहा, “चूंकि मामला शीर्ष अदालत में विचाराधीन है और न्यायालय ने स्थान पर पंहच जारी किया है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है।”

ऑनलाइन तरीके से होने वाली भर्तियों के चलते फर्जी डिग्री को लेकर नियोजताओं की चिंता बढ़ी : रिपोर्ट

मुंबई/भाषा। कार्यालय और घर दोनों जगह से काम करने (हाइब्रिड) की संस्कृति और अलग-अलग शहरों से हो रही भर्तियों के कारण, कर्मचारियों के व्योरे की केवल एक बार होने वाली जांच अब काफी नहीं लग रही है। शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, 74 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने फर्जी डिग्री और जाली दस्तावेजों को अपनी सबसे बड़ी चिंता बताया है।

कार्यबल और मानव संसाधन समाधान प्रदाता कंपनी ‘जीनियस एचआरटेक’ की रिपोर्ट के अनुसार, अब जब कंपनियां दूरदराज के इलाकों से बड़े पैमाने पर भर्तियां कर रही हैं और घर से काम करने का मॉडल (हाइब्रिड) सामान्य हो गया है, तो कर्मचारी की केवल एक बार की जाने वाली शुरुआती जांच अब काफी नहीं माना जा रही है।

दौरा



भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन गडकरी ने पदभार संभालने के बाद गोवा के अपने पहले दौरे के दौरान शुक्रवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक की अध्यक्षता की। गोवा के दो दिवसीय दौरे पर आए गडकरी ने मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, भाजपा की गोवा इकाई के अध्यक्ष दामोदर नाइक और अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बाद में यह पणजी में भाजपा मुख्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं को अपने संक्षिप्त संबोधन में गडकरी ने सभी को स्वागत के लिए धन्यवाद दिया और कोर कमेटी की बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं को 30 मिनट से अधिक समय तक संबोधित किया। पार्टी की कोर कमेटी में मुख्यमंत्री सावंत, नाइक, मंत्रीगण और चुनिंदा पदाधिकारी शामिल हैं।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा कानून नहीं चाहते प्रधानमंत्री: कांग्रेस



दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर नया कानून लाए जाने के विरोध में शुक्रवार को यात्रा निकाली और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऐसा कोई कानून नहीं चाहते जिसके साथ महात्मा गांधी नाम का जुड़ा हो। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने महात्मा गांधी की पुरुषतिथि पर, पार्टी के ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ के तहत

सर्वसम्मति से पारित हुआ था।” उन्होंने कहा कि मनरेगा कानून संवैधानिक हक था, लोगों के पास रोजगार की कानूनी गारंटी थी और इस कानून से पंचायतें मजबूत हुईं। रमेश ने दावा किया कि कानून रद्द कर दिया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं चाहते हैं कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा कानून ज्वादा समय तक चले और लोगों को उनका हक मिले। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा, “हम मोदी सरकार द्वारा मनरेगा के खिलाफ उठाए गए इस कदम का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। जो सरकार देश के किसानों, मजदूरों और युवाओं का अपमान करे, वह सत्ता में ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती।” देवेंद्र यादव ने कहा, “मनरेगा की लड़ाई देश के आम गरीब नागरिकों के रोजगार और हक की लड़ाई है, जिसे कांग्रेस पूरे देश में लड़ रही है। कांग्रेस की सरकार में गरीबों को हक मिला था- इज्जत और सम्मान के साथ रोटी कमाने का, गांव में रहकर काम करने का, जिससे उनके गांव का विकास हो। नरेन्द्र मोदी ने उसे खत्म कर दिया है।”



वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में 21 जनवरी तक मजबूत वृद्धि रही: गोयल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद इस साल 21 जनवरी तक देश से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, मंत्री ने इससे संबंधित आंकड़ों का खुलासा नहीं किया। ग्रेटर नोएडा में ‘आईसीआई वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा, “भारत का वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात इस साल 21 जनवरी तक लगातार बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि कड़ी मेहनत



ज्ञान, विनम्रता एवं निःस्वार्थ सेवा की भावना को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनायें : नायब सिंह सैनी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चंडीगढ़/भाषा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को युवाओं से ज्ञान, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा की भावना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आह्वान किया। सैनी ने कहा कि ये मूल्य भारत के महान गुरुओं के सच्चे संदेश और मार्गदर्शक मार्ग का सार हैं। यहां श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज के 61वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में

शामिल होकर उन्हें गर्व और सम्मान महसूस हो रहा है। इस कार्यक्रम सिखाओं के 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह के जीवन, शिक्षाओं और सर्वोच्च बलिदानों को समर्पित था। सैनी ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह को याद करने से एक ऐसे निखर योद्धा-संत की छवि उभरती है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता, धर्म और न्याय के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, “गुरु जी ने दुनिया को सिखाया कि सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया जा सकता, चाहे इसके लिए जान ही क्यों न देने पड़े। आत्मसम्मान और नैतिक साहस शाश्वत हैं।”

यूरोपीय संघ के साथ एफटीए से भारतीय निर्यातकों को मिलेगा बड़ा बाजार : मूडीज

नई दिल्ली/भाषा। मूडीज रेटिंग्स ने कहा कि यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ व्यापार समझौता भारत को अपने व्यापारिक संबंधों में विविधता लाने में मदद करेगा। साथ ही अमेरिकी शुल्कों के कारण बढ़ती अनिश्चितता के बीच निर्यातकों को व्यापक बाजार तक पहुंच मिलेगी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की घोषणा 27 जनवरी को की गई थी। इसके इसी साल हस्ताक्षरित और लागू होने की संभावना है। मूडीज ने कहा, “भारत के लिए, यह समझौता व्यापारिक संबंधों को सुनिश्चित रूप से विविधतापूर्ण बनाने के उसके प्रयासों को दर्शाता है। यह अमेरिकी के शुल्क बढ़ाने से पैदा होने वाली व्यापारिक अस्थिरता के खिलाफ बचाव प्रदान करता है।” इसमें कहा कि यूरोपीय संघ के लिए यह समझौता तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार तक पहुंच बढ़ाकर आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करता है।

अजित पवार के राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा तेज, सभी की नजर सुनेत्रा पर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



मुंबई/भाषा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र के दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा के पार्टी विधायक दल की नई नेता बर्धना पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस महत्वपूर्ण पद पर रिक्ति भरने से पहले परिवार की सहमति लेनी होगी। पटेल ने यह टिप्पणी पार्टी के कुछ नेताओं के उन बयानों के बाद की है कि राजस्वसभा सदस्य सुनेत्रा के राकांपा विधायक दल की नई नेता और साथ ही उपमुख्यमंत्री बनने की संभावना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पटेल ने कहा कि फिलहाल प्राथमिकता उपमुख्यमंत्री और राकांपा

विधायक दल के नेता के रिक्त पदों को भरना है। दोनों पद अजित पवार के पास थे जिनकी 28 जनवरी को विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि शीर्ष संगठनात्मक पद (दिवंगत अजित पवार पार्टी अध्यक्ष भी थे) पर नियुक्ति करना फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर उन्हें जानकारी दी है कि सत्तारूढ़ ‘महायुति’ में घटक राकांपा अपने नेतृत्व परिवर्तन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। पटेल ने

कहा, “अजित पवार राकांपा विधायक दल के नेता और सत्तारूढ़ महायुति के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे। हम नेतृत्व परिवर्तन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।” उन्होंने कहा कि राकांपा विधायक दल के नेता के रूप में अजित पवार के स्थान पर सुनेत्रा पवार के नाम का विरोध करने का कोई समाज ही नहीं उठता। सुनेत्रा पवार वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं और राज्य विधानसभा के किसी भी सदन की सदस्य नहीं हैं। हालांकि, अजित पवार के निधन के बाद पुणे जिले की बारामती विधानसभा सीट रिक्त हो गई है। पटेल ने कहा, “जनता और पार्टी की भावनाएं एक जैसी हैं। हमें (अजित पवार) के परिवार से (महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में) बात करनी होगी, पहले उनसे (मंजूरी के लिए) अनुरोध करना होगा।”



फर्जी फॉर्म-7 के मुद्दे को लेकर विधानसभा में हंगामा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान में मतदाता सुचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर बड़ी संख्या में फर्जी फॉर्म-7 दिए जाने के मुद्दे को लेकर शुक्रवार को विधानसभा में हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। शून्यकाल में कांग्रेस के विधायक ने इस मुद्दे को उठाना चाहा तो संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इस पर एतराज जताया। मंत्री के अनुसार यह राज्य अथवा राज्य सरकार से संबंधित विषय नहीं है इसलिए इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए तथा हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

बाद में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रकाश कि यह मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने के बारे में विधि विशेषज्ञों की राय के बाद फैसला लेंगे। कांग्रेस के विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने मकराना विधानसभा क्षेत्र में 14 से 19 दिसंबर के बीच प्राप्त फर्जी फॉर्म-7 की जांच करने व धरने के बावजूद सूची छिपाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने का मुद्दा पर्वी के जरिए उठाना चाहा।

जैसे ही हुसैन ने बोलना शुरू किया संसदीय कार्य मंत्री मंत्री



जोगाराम पटेल ने आपत्ति जताई। पटेल ने कहा कि विधायक ने पर्वी के जरिए उठाने के लिए जो विषय रखा है वह विषय नियमों व कायदे से यहां रखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि यह न तो राजस्थान सरकार का विषय है न ही राजस्थान सरकार से जुड़ा कोई विषय है। पटेल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-324 के तहत निर्वाचक नामावली से जुड़े काम निर्वाचन आयोग के अधीन आते हैं। मतदाता सूची बनाना, उसमें संशोधन, नाम जोड़ना या काटना ये सारे अधिकार निर्वाचन आयोग के पास हैं।

संसदीय कार्य मंत्री ने इस संबंध में अन्य नियमों का जिक्र करते हुए कहा कि यह राज्य सरकार की विषय वस्तु में नहीं आता है, और जो विषय राज्य सरकार का है ही नहीं उसे किसी भी तरह से विधानसभा में उठाना नहीं जा सकता। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने कहा कि जब मामला पर्वी के माध्यम से उठ गया है और सदन के अध्यक्ष की अनुमति से उठ गया तो संसदीय मंत्री कोन से नियमों की बात कर रहे हैं।

जुली ने कहा, हम तो पर्वी के

माध्यम से यह पूछ रहे हैं कि जो आवेदन आए व केहां से आए और उसकी जांच होगी या नहीं। हम तो चाहते हैं कि सरकार उसकी जांच करवा ले। इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री व नेता प्रतिपक्ष में तीखी नोक-झोंक हुई। मंत्री ने कहा कि इस विषय को यहां नहीं उठाना जा सकता। जुली ने इस मामले की जांच करवाने की मांग की। दोनों ओर के विधायक बोलने लगे तो विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश से पांच मिनट पहले दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

बाद में जब सदन की बैठक शुरू हुई तो जुली ने अध्यक्ष देवनानी से आग्रह किया कि चुनाव सुधारों के मुद्दे पर लोकसभा में हाल ही में चर्चा हुई है तथा उसके अनुसार यहां आधे घंटे की चर्चा करवाई जा सकती है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ऐसी चर्चा नियमों के अनुसार इस सदन में नहीं हो सकती। अध्यक्ष देवनानी ने कहा, मैं विधि विशेषज्ञों व संसदीय सचिवालय से चर्चा कर इस पर निर्णय करूंगा। इसके बाद सदन में आगे की नियमित कार्यवाही हुई।

संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार : भजनलाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन पर राज्य सरकार संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता के साथ आमजन की हर परियोजना के निरन्तरण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 के माध्यम से भी जनता की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निरन्तरण सुनिश्चित किया जा रहा है। शर्मा इस हेल्पलाइन का समय-समय पर निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि परिवारियों को त्वरित राहत मिले।

इसी कड़ी में शर्मा ने शुक्रवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन के माध्यम से आमजन से सीधा संवाद किया। शर्मा ने उनसे आत्मीयता से बात कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा अधिकारियों को उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आमजन से राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया।

शर्मा से कोटपुतली-बहरोड़ के मोहम्मदपुर नंगलिया खोहरी निवासी पिंकी यादव ने दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए

निवेदन किया। इसी तरह डूंगरपुर के बोड़ीगामा छोटा गांव से जितेन्द्र ने जाति प्रमाण पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बनने के संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। वहीं प्रतापनगर, जयपुर की निवासी लाजवती ने मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में निवेदन किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इनकी समस्याओं का समाधान कर राहत देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री को रतनगढ़ चूरू के भोजासर से किशनलाल ने मकान का पट्टा जारी नहीं होने तथा ग्राम पंचायत स्तर पर लंबित होने की जानकारी दी। किशनलाल ने शर्मा से शीघ्र पट्टा जारी करवाने का आग्रह किया। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इनके मकान का

पट्टा जारी करने के लिए निर्देशित किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली, शिकायत पंजीकरण की प्रणाली तथा फॉलो-अप प्रक्रिया की पूरी जानकारी ली। शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए संपर्क पोर्टल पर आ रही समस्याओं की अधिक से अधिक मॉनिटरिंग हो, जिससे परिवर्ती की समस्या का समयबद्ध निरन्तरण हो सके। मुख्यमंत्री को नेतृत्व में जनसेवा को सर्वोपरि मानते हुए राज्य सरकार कार्य कर रही है। इसी दिशा में 181 हेल्पलाइन के माध्यम से आमजन घर बैठे अपनी समस्या दर्ज करवाकर उसका शीघ्र समाधान प्राप्त कर रहे हैं।

राजस्थान में सरकारी स्कूलों के 3,768 भवन जर्जर स्थिति में : मदन दिलावर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान में सरकारी स्कूलों के 3,768 भवन जर्जर हालत में पाए गए हैं। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि झालावाड़ में सरकारी स्कूल भवन के एक हिस्से के गिरने से सात बच्चों की मौत हो गई थी।

इसके बाद राज्य भर के सरकारी स्कूलों के भवनों का जिला स्तरीय सर्वेक्षण करवाया गया। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक संदीप शर्मा के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि जिलाधिकारियों के माध्यम से करवाए गए जिला-स्तरीय सर्वेक्षण



के अनुसार राज्य के 3,768 स्कूल भवन जर्जर स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि उक्त सर्वेक्षण में 3,768 विद्यालयों के भवनों को जर्जर चिन्हित किया था। इसमें से 2,558 को जर्जर घोषित किया जा चुका है। शेष 1,210 भवनों को जर्जर घोषित किया जाना है। इन विद्यालयों के भवनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मंत्री के अनुसार उक्त सर्वेक्षण के अनुसार 45,365 राजकीय विद्यालयों में से

41,178 विद्यालयों में व्यापक स्तर पर मरम्मत कार्य की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि राज्य मद (वर्ष 2025-26) अंतर्गत 2,000 राजकीय विद्यालयों के लिए मरम्मत कार्य हेतु 17497.51 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

इसके अलावा जिलाधिकारियों द्वारा बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के लिए राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) में 20,383 विद्यालयों की मरम्मत के कार्य स्वीकृत हैं। विभाग द्वारा जिन 3,768 विद्यालयों के भवनों को जर्जर चिन्हित किया गया है उनसे प्रथम चरण में 1,680 विद्यालयों में नए भवन के लिए 1998.24 करोड़ रुपये के प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे गए हैं।

राजस्थान के कई इलाकों में आज से बारिश का अनुमान

जयपुर। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के कई इलाकों में शनिवार से बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 31 जनवरी को राज्य के अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। एक ओर दो फरवरी को भी उत्तरी व पूर्वी राजस्थान के अजमेर, कोटा, जयपुर व भरतपुर संभाग में आकाशीय बिजली के साथ कहीं-कहीं हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में मौसम के मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है।

इस बीच राज्य में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। शनिवार सुबह कई इलाकों में कोहरा छाया रहा।



प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान योजना की राज्य स्तरीय एपेक्स कमेटी की बैठक आयोजित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, अंतरविभागीय समन्वय एवं प्रगति की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय एपेक्स कमेटी की बैठक शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक के अध्यक्षता मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की। बैठक में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा पीएम जनमन योजना के अंतर्गत राज्य में संचालित विभिन्न हस्तक्षेपों की विस्तृत प्रगति से अवगत कराया गया। मुख्य सचिव ने बैठक में निर्देश दिए कि पीएम जनमन योजना के सभी हस्तक्षेपों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ सहायिका जनजाति के जीवन स्तर में स्थायी सुधार लाया जाए। उन्होंने कहा कि यह योजना सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक

महत्वपूर्ण पहल है।

बैठक में बताया गया कि राजस्थान में विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह के रूप में केवल सहायिका जनजाति निवासरत है, जो मुख्यतः बारां जिले के किशनगंज एवं शाहबाद ब्लॉकों में केंद्रित है। जिले में सहायिका जनसंख्या लगभग 1.30 लाख है, जो 424 बसावटों एवं 324 राजस्व ग्रामों में निवास करती है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान योजना के अंतर्गत सहायिका परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से संतुष्ट करने की दिशा में ठोस प्रगति दर्ज की गई है। बैठक में पक्षे आवास निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि चयनित मॉडल ग्रामों में आवासीय सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया गया है। बारां जिले के भवतीपुरा जैसे ग्रामों में मॉडल कॉलोनियों का निर्माण कर सुरक्षित और समानजनक आवास उपलब्ध कराया गया है, जिससे सहायिका परिवारों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सड़क संपर्कता के क्षेत्र में पीएमजीएसवाई

के अंतर्गत सहायिका बहुल 39 बसावटों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। विभिन्न ग्रामों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण से आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका के अवसरों में सुधार आया है। स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से दूरस्थ बसावटों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं तथा नियमित चिकित्सा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

बैठक में शिक्षा से जुड़े हस्तक्षेपों की भी समीक्षा की गई। सहायिका विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण एवं संचालन किया जा रहा है, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकें। विद्युतीकरण के क्षेत्र में बताया गया कि जिले में 17,633 लक्षित परिवारों में से 16,023 परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं और शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सहायिका परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने की दिशा में

उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अधिकांश बसावटों में 100 प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण एवं संचालन के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया गया है।

आजिविका संवर्धन के लिए वन धन विकास केंद्रों की स्थापना की गई है, जहां स्व-सहायता समूहों को आजीविका से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण कर सामुदायिक गतिविधियों के लिए आधारभूत ढांचा विकसित किया गया है। दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार हेतु मोबाइल टावर स्थापना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक में कौशल विकास के अंतर्गत सहायिका युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पीएमकेवीआई के तहत 500 युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना पर चर्चा की गई। अब तक सैकड़ों युवाओं का जीविकोपार्जन प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है, जिससे उन्हें भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।



युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर 'विकसित भारत' के निर्माण में योगदान दें: अर्जुनराम मेघवाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। केन्द्रीय विधि व न्याय एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री तथा जैन विश्वभारती के प्रधान मेघवाल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर असीम ऊर्जा का भंडार होता है, आवश्यकता केवल उसे सही दिशा में नियोजित करने की है। वे यहाँ जैन विश्वभारती (मान्य विश्वविद्यालय) में विभिन्न नवनिर्मित परियोजनाओं के उद्घाटन व लोकार्पण समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित कर रहे थे। विद्यार्थियों को जीवन के व्यावहारिक सूत्र देते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि 12 से 17 वर्ष की किशोरावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस आयु में

अपनाए गए अच्छे या बुरे संस्कार व्यक्ति के संपूर्ण भविष्य का निर्धारण करते हैं। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के लिए गणित, तनाव मुक्ति के लिए संगीत और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खेलों को जीवन का हिस्सा बनाने की सीख दी।

समारोह के दौरान मेघवाल ने

कुलपति प्रो. बच्छराज दुगड़ के साथ मिलकर विश्वविद्यालय की नवीन डिजिटल और भौतिक अवसंरचनाओं का लोकार्पण किया: 'मोबाइल कनेक्ट' एप्लिकेशन, एल्यूमीनी नेटवर्क पोर्टल और लॉगिन मैनेजमेंट सिस्टम (डचड) की शुरुआत। आचार्य महाप्रज्ञ

आईसीडीएस निदेशालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी गई श्रद्धांजलि

जयपुर। शहीद दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जयपुर स्थित निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं मुख्यालय परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनके चित्र पर माल्यार्पण कर, तथा दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। आईसीडीएस निदेशक वासुदेव मालावत ने इस अवसर पर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने एक राष्ट्र के रूप में हमारी सुप्त चेतना को जागृत किया। उन्होंने कहा कि हमारी राष्ट्रीय चेतना में विभिन्न धाराएं समाहित हैं तथा गांधी जी उनका प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने अखंड असहनीय पीड़ाएँ सहकर और कठिन संघर्ष से स्वतंत्रता प्राप्त की है और देश आज संगठित और सार्थक मार्ग पर अग्रसर है।

प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र में नवनिर्मित डीलक्स ब्लॉक, व्यायामशाला, आवासीय क्वार्टर और सत्कार अतिथि गृह का उद्घाटन। मेघवाल ने संस्थान के संस्थापक आचार्य तुलसी की दूरदर्शिता की सराहना करते हुए कहा कि इस परिसर में आज भी उनकी नैतिक ऊर्जा का अनुभव होता है। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि 21वीं शताब्दी एशिया और विशेषकर भारत के नेतृत्व की शताब्दी है। इस अवसर पर उन्होंने स्वरचित कविता 'हम हैं भारत के लोग' का गान कर सहयोग का अंतरराष्ट्रीय मंच बनाया। कर्नल राठौड़ विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति का उत्साह भरा। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी मीनू रमा, जैन विश्व भारती के अध्यक्ष अमरचंद लूंकड, प्रमोद बैद, प्रकाश बैद, टीकमचंद सेठिया सहित विश्वविद्यालय का स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित रहे।

इंडिया स्टोनमार्ट 2026 प्रदेश की निवेश संभावनाओं को परफॉर्मेंस में बदल रही राज्य सरकार : राठौड़

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि इंडिया स्टोनमार्ट के आयोजन से राजस्थान के पथर उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश के कारीगरों को देश-विदेश में इस क्षेत्र की नवीनतम तकनीक की जानकारी मिल सकेगी। रीको, सीडोस और लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह कार्यक्रम नीति संवाद, तकनीक और वैश्विक सहयोग का अंतरराष्ट्रीय मंच बनाया। कर्नल राठौड़ विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति का उत्साह भरा। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी मीनू रमा, जैन विश्व भारती के अध्यक्ष अमरचंद लूंकड, प्रमोद बैद, प्रकाश बैद, टीकमचंद सेठिया सहित विश्वविद्यालय का स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित रहे।



का इस वर्ष 13वां संस्करण है। यह अब तक का सबसे भव्य आयोजन होगा। इसमें चीन, तुर्की, ईरान, थाइलैंड, इटली सहित अन्य देशों से प्रदर्शकों की शामिल होंगे।

कर्नल राठौड़ ने बताया कि आयोजन में राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद के तहत चयनित पथर के उत्पादों के प्रदर्शन के लिए एक विशेष पवेलियन बनाया जाएगा। इससे प्रदेश के इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। इससे इन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। कर्नल राठौड़ ने कहा कि राजस्थान को स्पष्ट नेतृत्व और नीति से नई दिशा मिली है। पिछले दो साल

में निवेश प्रोत्साहन के लिए नई नीतियां और योजनाएं लागू की गई हैं। राज्य सरकार के इन प्रयासों के कारण राजस्थान एक बेहतरीन निवेश गंतव्य बन गया है। राइजिंग राजस्थान के तहत किए गए 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू पर काम शुरू हो गया है।

कर्नल राठौड़ ने कहा कि पिछले दो वर्ष में राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बेहतर काम किया है। अब तक राजकीय क्षेत्र में एक लाख से अधिक युवाओं को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और 1.54 लाख पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निवेश समझौतों को धरातल पर उतारा जा रहा है। इस क्रम में राइजिंग राजस्थान, प्रवासी राजस्थानी दिवस का सफल आयोजन किया गया है। साथ ही, प्रदेश के युवाओं को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा हाल ही में नई योजना लागू की है।

सुविचार

एक गलती आपका अनुभव बढ़ा देती है और एक अनुभव आप की गलतियों को कम कर देता है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

सेलिब्रिटी नहीं, जनसेवक बनें

बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग के संबंध में जो नियमावली तैयार की है, उसकी बहुत जरूरत महसूस की जा रही थी। अन्य राज्यों को भी ऐसी नियमावली तैयार कर अनुशासन का माहौल बनाना चाहिए। हाल के वर्षों में ऐसे मामले सामने आए, जब कुछ सरकारी कर्मचारी अपना कर्तव्य निभाने के बजाय सोशल मीडिया के लिए सामग्री तैयार करने में ज्यादा व्यस्त रहे। ये कर्मचारी फिल्मी संवाद दोहराते हैं, गानों पर नृत्य करते हैं और अपने वीडियो वायरल कर वाहवाही पाने की कोशिश करते हैं। उनमें से कुछ तो अपनेआप को बड़ी सेलिब्रिटी समझने लगते हैं, जबकि ऐसी हरकतें उस विभाग की छवि को धूमिल करती हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे अधिकारी और कर्मचारी मिल जाएंगे, जो जनता के बीच मशहूर होने के लिए खास किस्म के तौर-तरीके अपनाते हैं। एक अधिकारी वीडियो एडिटिंग की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर खुद को ऐसे पेश करते हैं, जैसे वे कोई सम्राट हों। वे अपने वाहन से उतरने, चलने और दफ्तर में दाखिल होने को किसी फिल्म की तरह दिखाते हैं। ऐसे मीडियो का शीर्षक कुछ इस तरह होता है- ‘पावर ऑफ ... ऑफिसर, यह होती है ताकत, दुनिया करती है सैल्यूट!’ इसका किशोरों और युवाओं पर खासा रोंब पड़ता है। वे सोचते हैं कि इन लोगों को सच में ही सारी दुनिया सैल्यूट करती है। सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों का काम है- जनता की सेवा करना, सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना। जो व्यक्ति अपना समय और ऊर्जा वीडियो बनाने में ही लगाएगा, वह अपने काम को कितने मनोयोग से कर पाएगा?

कुछ अधिकारी व कर्मचारी आत्मप्रचार से दूर रहकर ऐसे विषयों पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, जिनसे जनता को बहुत फायदा होता है। एक पुलिस अधिकारी साइबर सुरक्षा संबंधी मामलों के विशेषज्ञ हैं। उनका हर वीडियो ज्ञानबद्धक होता है। वे लोगों को साइबर ठगी से सुरक्षित रहने के तरीके बताते हैं। रेलवे के एक कर्मचारी बहुत आसान भाषा में जानकारी देते हैं। टिकट कैसे बुक कराएं, किस ट्रेन में कौनसी सुविधाएं होती हैं, यात्रा के दौरान कोई समस्या आए तो किससे संपर्क करें - जैसे सवालों के जवाब मिलने से लोगों की जानकारी में बढ़ोतरी होती है। इसी तरह डाक विभाग के एक कर्मचारी लघु बचत योजनाओं के विशेषज्ञ माने जा सकते हैं। किसके लिए कौनसी बचत योजना बेहतर है, लंबी अवधि में किस योजना में निवेश करें, कर्फी निवेश योजनाओं से कैसे बचें - के बारे में वीडियो ‘गामरों से सागर’ होते हैं। एक यातायात पुलिसकर्मी अपने विभाग की आदर्श छवि पेश करते हैं। वे लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सभी नियमों का पालन करता है तो उसकी तारीफ करते हैं। इसके अलावा, यातायात संबंधी दस्तावेज बनवाने के लिए जानकारी देते हैं। ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित करना चाहिए। ये जनता तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाते हैं और सरकार की योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। सर्वसमाज को उनके ज्ञान और अनुभव का फायदा मिलता है। अगर हर क्षेत्र में कुछ अधिकारी व कर्मचारी ऐसी उपयोगी सामग्री का निर्माण करें तो लोगों को योजनाओं से जुड़ने में बहुत आसानी हो सकती है। जो लोग सिर्फ आत्मप्रचार के लिए डेरों तस्वीरें-वीडियो पोस्ट करते रहते हैं, सिर्फ अपनी छवि बनाने में व्यस्त रहते हैं, खुद को किसी सेलिब्रिटी की तरह दिखाते हैं, हमेशा आत्ममुग्ध रहते हैं, उन्हें सरकार की ओर से सख्त नसीहत मिलनी चाहिए।

ट्वीटर टॉक

वसुंधरा राजे

धर्म, स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा हेतु जीवनभर 80 से अधिक युद्धघाव सहकर भी अदम्य साहस के साथ आक्रमणकारियों का सामना करने वाले राणा सांगा जी का शौर्य और बलिदान युगों-युगों तक राष्ट्र को प्रेरणा देता रहेगा।

महिला सशक्तीकरण की दिशा में यह निर्णय मील का पथर साबित होगा। मुझे आशा है कि केन्द्र सरकार भी राजस्थान की तर्ज पर पूरे देश में सिर्फ बालिकाओं ही नहीं सभी महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने की योजना लागू करेगी।

अशोक गहलोत

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। सत्य पर अडिग विश्वास और अहिंसा में अपार शक्ति है। बापू के आदर्शों से ही हिंसक और नकारात्मक सोच को मिटाकर देश को नई राह दिखाई जा सकती है।

गोविंदसिंह डोटोसरा

प्रेरक प्रसंग

भक्ति निस्वार्थ भाव से ही करनी चाहिए

पूजा करते समय अधिकतर लोग भगवान से सुख-सुविधाओं से जुड़ी पाने की कामना करते हैं। पूजा के बदले भगवान से कुछ न कुछ मांगा जाता है। इस तरह की भक्ति करने के बाद जब मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो मन अशांत हो जाता है। मन की शांति चाहिए तो भक्ति निस्वार्थ भाव से ही करनी चाहिए। ये बात एक लोक कथा से समझ सकते हैं। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि अगले दिन जो भी व्यक्ति मेरे महल की जिस चीज पर हाथ रख देगा, वह उस की हो जाएगी। राजा की घोषणा सुनकर प्रजा खुश थी। सभी राजा की अलग-अलग कीमती चीजों को पाना चाहते थे। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई राजा के महल में प्रजा की भीड़ लग गई। कुछ लोग सोने-चांदी के बर्तन लेने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ लोग हिर-मोती के आभूषण लेने लगे। राजा दूर अपने सिंहासन पर बैठकर ये नजारा देख रहे थे। उनकी प्रजा महल की चीजों को पाने के लिए दौड़भाग कर रही थी। तभी एक व्यक्ति राजा की ओर बढ़ रह था। वह राजा के पास पहुंचा और उसने राजा पर हाथ रख दिया।

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s, New Media Company,6/4 , 1st floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasadur Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. Editor-Shreekant Parashar. (*Responsible for selection of news under PRB Act). Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.RNI No. 58061/93. Regn.No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वगैरह, टैंडर एवं सजायटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी यह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पातों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रण एवं प्रकाशक या मालिकाना को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता। - दक्षिण भारत राष्ट्रमत

सामयिक

यूजीसी नियमों पर न्यायिक विराम

ललित गर्ग

मोबाइल : 98110511

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता के नाम पर लागू किए गए नए नियमों ने देश के शैक्षिक और सामाजिक परिदृश्य में एक बार फिर गहरी हलचल पैदा कर दी है। जिस ‘नीति को समता’, ‘समान अवसर’ और ‘समावेशी शिक्षा’ की भावना से जोड़कर प्रस्तुत किया गया, वह व्यवहार में आते ही एक वर्ग विशेष के तीव्र विरोध, व्यापक असंतोष और सामाजिक तनाव का कारण बन गई। स्थिति इतनी विकट हुई कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप कर इन नियमों पर अंतरिम रोक लगानी पड़ी। यह रोक न केवल सरकार की नीति-निर्माण प्रक्रिया पर एक प्रश्नचिह्न है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिशयोक्तिपूर्ण और असंतुलित प्रयोग देश को किस दिशा में ले जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप किसी नीति के समर्थन या विरोध का सीधा निर्णय नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक चेतावनी है कि समानता के नाम पर लागू किए गए नियम यदि अस्पष्ट हों, दुरुपयोग की संभावना रखते हों और सामाजिक सौहार्द को बाधित करते हों, तो वे न्यायिक समीक्षा से परे नहीं रह सकते। अदालत ने प्रथम दृष्टया यह माना कि यूजीसी के नए नियमों में स्पष्टता का अभाव है और यही अस्पष्टता उन्हें विवादास्पद बनाती है। यह रोक सरकार को आत्ममंथन का अवसर देती हैकृएक ऐसा अवसर जिसे राजनीतिक टकराव के बजाय सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रश्न यह है कि जो सरकार बार-बार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती रही है, वह शिक्षा संस्थानों जैसे विचार-निर्माण के केंद्रों में ऐसे नियम क्यों लाई, जिनसे जातिगत पहचान और वर्गीय विभाजन की रेखाएँ और गहरी होने की आशंका पैदा हो गई। भारत का सामाजिक इतिहास इस

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NO T PRIVATE of EDU

EJECT UGC NEW ACT REGULATIONS!

WITHDRAW UGC NEW ACT

तथ्य का साक्षी है कि जाति के नाम पर की गई किसी भी नीति ने, चाहे उसका उद्देश्य कितना ही कल्याणकारी क्यों न रहा हो, समाज को भीतर ही भीतर विभाजित किया है। आरक्षण जैसी संवैधानिक व्यवस्था सामाजिक न्याय के लिए लाई गई थी, लेकिन इसके लंबे प्रयोग ने देश को ऐसे घाव भी दिए हैं, जिनका उपचार आज तक पूर्ण रूप से नहीं हो सका। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में जातिगत आधार को और उभारने वाली किसी भी पहल को लेकर स्वाभाविक रूप से आशंका उत्पन्न होती है।

शिक्षा संस्थान केवल डिग्री बांटने की फैक्ट्रियाँ नहीं होते; वे समाज की दिशा तय करने वाली प्रयोगशालाएँ होते हैं। यहां तैयार होने वाला छात्र केवल नौकरीपेशा व्यक्ति नहीं, बल्कि भविष्य का नागरिक होता है। यदि यही परिसर अविश्वास, वर्ग-संघर्ष और परस्पर शंका के केंद्र बन जाएं, तो इसका प्रभाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह सामाजिक ताने-बाने को भी कमजोर करता है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर उठा विरोध इसी आशंका का प्रकटीकरण है। यह भी विचारणीय है कि समानता और समता के बीच का अंतर नीति-निर्माण में किस हद तक समझा गया। समानता का अर्थ है सबके साथ एक जैसा व्यवहार, जबकि समता का अर्थ है परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुलित अवसर देना। यदि

समता के नाम पर ऐसे प्रावधान किए जाएं जो एक नए प्रकार की असमानता को जन्म दें, तो वह नीति अपने उद्देश्य से भटक जाती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इसी बिंदु की ओर संकेत करती है कि नियमों का उद्देश्य भले ही सकारात्मक रहा हो, लेकिन उनकी संरचना और भाषा ने विवाद और भ्रम को जन्म दिया।

यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पूरे मामले में राजनीतिक रंग तेजी से हावी होता गया। पक्ष और विपक्ष दोनों ने इसे अपने-अपने हितों के चश्मे से देखना शुरू कर दिया, वोट बैंक की राजनीति से इसे देखा जाने लगा जबकि यह विषय मूलतः शिक्षा सुधार और सामाजिक संतुलन से जुड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कई अवसरों पर यह कहते रहे हैं कि शिक्षा को राजनीति से मुक्त रखा जाना चाहिए और नीतियाँ दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर बननी चाहिए। फिर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यूजीसी द्वारा बनाए गए इन नियमों में उस दूरदर्शिता और संतुलन का अभाव क्यों दिखा? लगता है कि यूजीसी ने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे इसे लागू कर दिया,यदि यूजीसी ने व्यापक संवाद, सभी पक्षों से परामर्श और संभावित दुरुपयोग की आशंकाओं का पूर्व अकलन किया होता, तो शायद यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। नीति बनाते समय केवल कानूनी वैधता पर्याप्त नहीं होती; सामाजिक

स्वीकार्यता और नैतिक संतुलन भी उतने ही आवश्यक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश के माध्यम से यही संकेत दिया है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी बदलाव से पहले उसके दूरगामी प्रभावों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

नए नियमों की सबसे बड़ी कमजोरी एवं त्रासदी यही रही कि वे आरक्षित और सामान्य वर्गों को एक-दूसरे के सामने खड़ा करके विद्रोह एवं विरोध में खड़ा कर दिया। यह विभाजनकारी प्रवृत्ति न केवल शिक्षा के वातावरण को दूषित करती है, बल्कि उस राष्ट्रीय एकता की अवधारणा को भी कमजोर करती है, जिसकी बात हम संविधान में करते हैं। किसी भी नीति का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि वह समाज को जोड़ती है या तोड़ती है। यदि वह अविश्वास और टकराव को बढ़ावा देती है, तो उस पर पुनर्विचार अनिवार्य हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक सुधार का अवसर है-सरकार, यूजीसी और सम्बद्ध शैक्षिक तंत्र के लिए। यह समय है कि भावनाओं और राजनीतिक आग्रहों से ऊपर उठकर एक ऐसी नीति बनाई जाए, जो वास्तव में समान अवसर सुनिश्चित करे, लेकिन बिना किसी नए विभाजन को जन्म दिए। शिक्षा में सुधार का अर्थ समाज को आगे ले जाना है, न कि पुराने घावों को फिर से कुरेदना।

देश को ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता है जो प्रतिभा को जाति से ऊपर रखे, अवसर को पहचान से मुक्त करे और परिसरों को संघर्ष का नहीं, संवाद का केंद्र बनाए। सुप्रीम कोर्ट की यह रोक उसी दिशा में एक संकेत है। अब यह सरकार और यूजीसी की जिम्मेदारी है कि वे इस संकेत को समझें, आत्मवालोचन करें और ऐसे नियम गढ़ें जो वास्तव में भारत की समावेशी, संतुलित और भविष्यद्रष्टा संरचना के अनुरूप हों। यदि इस अवसर को भी राजनीतिक स्वार्थ की भेंट चढ़ा दिया गया, तो यह केवल एक नीति की विफलता नहीं होगी, बल्कि उस विश्वास की भी हार होगी, जो जनता ने शिक्षा सुधारों से जोड़ रखा है।

विशेष

जातिवादी राजनीति का दुष्चक्र

डॉ. कृष्णा अनुराग

केंद्र में सत्तासीन पार्टी, जो 'एक हैं तो सेफ हैं', 'बंटेंगे तो कटेंगे' जैसे नारे दिए और अचानक यह जातिवादी गंदी राजनीति के माध्यम से सवर्णों और अन्य जातियों के बीच विष उत्पन्न करने वाले यूजीसी के नए अधिनियम लेकर आ गई।हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस पर रोक लगाकर एक बार तो देश को जातिगत आग में झोंके जाने से बचा लिया है।

यूजीसी-2026 के नए अधिनियमों का चौतरफा विरोध हो रहा है और देश के शिक्षा मंत्री कर रहे हैं कि 'नियमों का दुरुपयोग कोई भी नहीं कर पाएगा।' सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसे नियम ही क्यों बनाए गए जो एक वर्ग के मन में डर पैदा करें? यूजीसी के नए नियमों का लब्धोलुआब यह है कि बिना किसी जांचपड़ताल के पहले ही मान लिया गया है कि सामान्य वर्ग के बच्चे शोषक और तथाकथित पिछड़े और दलित वर्ग के बच्चे शोषित हैं। विदित हो कि देश के विश्वविद्यालयोंमहाविद्यालयों में वर्ष 2012 से ही दलितों के शोषण और उत्पीड़न पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद यूजीसी स्वयं मानती है कि दलितों के साथ भेदभाव और

उत्पीड़न पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ा है। ऐसे में यह बात स्पष्ट है कि नए नियमों से अधिक इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि कैसे हर वर्गियों के बच्चों के बीच दूरियाँ मिटे। आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद अगर आज तक समाज में आरक्षण आदि के बाद भी समरसता नहीं आई है तो इस संबंध में नए ढंग से पुनर्विचार करने की जरूरत है। सरकारोंनेताओं को यह समझना होगा कि तुष्टिकरण की राजनीति से समाज में भेदभाव और बढ़ेगा। बच्चे जाति देख कर दोस्ती करेंगे और दूरियाँ बढ़ाएंगे, वैमनस्य की खाई और गहरी होगी। समाज अगर खंडखंड में विभाजित होगा तो भविष्य में वह देश के लिए ही घातक होगा।

आज देश में आतंकवाद, हत्या, बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, आदि घृणित कार्यों के मद्देनजर अनेक कठोर कानूनों का प्रावधान किया गया है, इसके बावजूद तमाम तरह की वीभत्स घटनाएँ लगातार हो रही हैं। स्पष्ट है कि सिर्फ कानून इस तरह की गतिविधियों को नहीं रोक सकता है। जरूरत है ऐसी शिक्षा की जो नैतिक मूल्यों पर आधारित हो, जिसका मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास हो। जब विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के कैंपसों में भेदभाव की बात हो रही है तो क्यों नहीं बचपन से ही ऐसी शिक्षा की बात हो जो हर किसी को जोड़े ? यह सर्वविधित

है कि सनातन भारतीय समाज में हर जाति का अपना महत्त्व रहा है। जन्ममृत्यु, विवाह आदि के क्रियाकलापों में यह देखा जा सकता है कि हर जाति के लोग किस तरह से इन आयोजनों में न केवल शामिल होते हैं, बल्कि उनके बिना कर्मकांड अधूरा ही माना जाता है।

इस बात को मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि अतीत में कुछ ऐसी सामाजिक रूप से विदूष घटनाएँ घटी हैं जो सनातन मूल्यों के खिलाफ कही जा सकती हैं। निश्चित रूप से उससे सीख ले कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है।दुर्भाग्य से आज भारत के तमाम राजनीतिक दल पुनः उसी जातिगत दलदल में धंसने की कोशिश कर रहे हैं। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जिन सवर्ण बच्चों ने कोई घृणित हरकत नहीं की है, उन्हें केवल इस लिए 'फँसाने' की बात तथाकथित बहुजन चिंतकों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि उनके पुरखों ने सदियों पहले कथित रूप से दलितपिछड़े वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव किया था। पूर्वपिछे के द्वारा किए गए किसी भी कार्य की सजा उनके बच्चों को नहीं दी जा सकती है। यद्यपि अभी पूरे देश में जातीय जनगणना नहीं हुई है, इसके बावजूद यह माना जाता है कि सवर्णों की आबादी इस देश में लगभग 12 से 15 प्रतिशत है और दलितोंपिछड़ों की आबादी 8085 प्रतिशत। ऐसे में जातीय तौर पर अल्पसंख्यक सवर्णों की चिंताओं पर निश्चित

रूप से विचार किया जाना चाहिए। अच्छा तो यह होता कि देश जातिविहीन समाज की ओर आगे बढ़ता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी विवादित यू.जी.सी. अधिनियम 2026 पर स्टे लगाते हुए यही बात कही है। केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए नेताओं को विभाजन के नवीन प्रयासों से बचना चाहिए। यह देश हर वर्ग, जाति और धर्म से जुड़े लोगों का है। आदि काल से भारत ने खुली बाहों से हर किसी का स्वागत किया है। ऐसी स्थिति में हमें अपने सनातन मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए।

जब विश्व की तमाम महाशक्तियाँ अनुसंधान और नवाचार में व्यस्त हैं, भारत में जाति को लेकर बहस एक बार फिर गर्म हो गई है। कुछ दिनों तक सड़कों पर तथाकथित अगड़ों ने आंदोलन किया, संभव है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पिछड़े झंडापताका ले कर सड़कों पर आरेंगे। देश के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसी स्थितियाँ निराशाजनक हैं। अब जाति के आधार पर भेदभाव न हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए और यह कानून से नहीं, नैतिक शिक्षा से ही संभव है। जातिविहीन समाज यत्न की जरूरत है तभी सच्चे अर्थों में देश अपने दूरगामी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगा।

✽ लेखक बीएमएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, बेंगलूरु के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं।

ज्ञान विज्ञान

अंतरिक्ष में जल्द दिखेगा सुपरमून का दिलचस्प नजारा

खगोलविज्ञानियों और अंतरिक्ष में दिलचस्पी रखने वालों को जल्द ही बेहद शानदार नजारे का दीदार होने वाला है। 5 नवम्बर बुधवार को आसमान में चांद थोड़ा और बड़ा और चमकीला दिखाई देगा। ऐसा सुपरमून की वजह से हो रहा है। सुपरमून तब होता है जब पृथ्वीमा का चांद अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कहना है कि इस वजह से चांद साल के सबसे धुंधले चांद की तुलना में 30% ज्यादा चमकीला और 14% बड़ा दिखाई देता है। दरअसल, चंद्रमा पृथ्वी चक्कर लगाता है लेकिन यह कक्षा पूर्ण वृत्ताकार नहीं है।

सलिए जैसे-जैसे यह परिक्रमा करता है, नजदीक और दूर होता जाता है। 5 नवम्बर को होने वाला सुपरमून इस साल के तीन सुपरमून में से दूसरा और सबसे नजदीकी है। इस दौरान चांद पृथ्वी से लगभग 357000 किलोमीटर की दूरी पर होगा। लोवेल ऑब्जर्वेटरी के खगोलशास्त्री लॉरेंस वासरमैन का कहना है कि सुपरमून के दौरान समुद्र में ज्वार थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि चांद पृथ्वी के ज्यादा नजदीक होगा। हालांकि, यह अंतर

ज्यादा दिखाई नहीं देगा। अगर आसमान साफ हो तो सुपरमून देखने के लिए किसी विशेष उपकरण की जरूरत नहीं होती।

हालांकि, चंद्रमा के आकार में परिवर्तन को नंगी आंखों से देख पाना कठिन हो सकता है। खगोल विज्ञानियों का कहना है कि यह अंतर अन्य तस्वीरों या अवलोकनों की तुलना में सबसे साफ होता है। सुपरमून शब्द पहली बार 1979 में खगोलशास्त्री

रिचर्ड नोले ने इस पूर्ण चंद्रमा के लिए इस्तेमाल किया था, जो साफ तौर पर बड़े और चमकीले दिखाई देते हैं। नवम्बर का बीच मून इस साल पृथ्वी का सबसे निकटतम पूर्ण चंद्रमा होगा, इसलिए यह सबसे चमकीला होगा और सबसे बड़ा दिखाई देगा।

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s, New Media Company,6/4 , 1st floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasadur Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. Editor-Shreekant Parashar. (*Responsible for selection of news under PRB Act). Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.RNI No. 58061/93. Regn.No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वगैरह, टैंडर एवं सजायटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी यह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पातों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रण एवं प्रकाशक या मालिकाना को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता। - दक्षिण भारत राष्ट्रमत



खेल को भोजन की तरह रोजमर्रा की आदत बनाइए : रीथ अब्राहम

जीतो लेडीज विंग का 30 दिवसीय 'फिटनेस फिएस्टा' सम्पन्न

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। जीतो लेडीज विंग साउथ द्वारा माह भर चले फिटनेस एवं वेलनेस अभियान 'फिटनेस फिएस्टा' का समापन गुरुवार को हुआ। इस अवसर पर 'फिटनेस-मिथ एंड मिरर्री' विषय पर आयोजित विशेष सत्र ने उपस्थित सदस्यों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। लेडीज विंग की चेयरपर्सन बबीता रायसोनी ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि हमने फिटनेस फिएस्टा में जीतो के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए स्वास्थ्य सेवा, ज्ञान जागरूकता और महिलाओं के पुनरुत्सर्जन का कार्य किया। जीतो साउथ के चेयरमैन रणजीत सोलंकी ने कहा कि लेडीज विंग व प्रतिभागियों की निरंतर व सक्रियता ने ही फिटनेस फिएस्टा को ऐतिहासिक सफलता दिलाई। अपेक्स डायरेक्टर नरेंद्र सामर ने कहा कि स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और इस दिशा में जीतो लेडीज विंग द्वारा किए जा रहे प्रयास प्रेरणादायक हैं। केकेजी संयोजिका पिंकी जैन ने भी कार्यक्रम की

सराहना की। झ्रङ्ग कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित 'अर्जुन पुरस्कार' विजेता रीथ अब्राहम ने अपने संघर्षपूर्ण खेल जीवन की जानकारी साझा करते हुए कहा कि खेल में थकान जरूर होती थी, लेकिन कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि जब आप अपने काम से प्यार करते हैं, तो थकान भी आनंद बन जाती है। अगर शरीर स्वस्थ है, तभी हम अपने जीवन की हर उपलब्धि का असली आनंद ले सकते हैं। खेल को भोजन की तरह रोजमर्रा की आदत बनाइए, जैसे हम एक दिन भी खाना नहीं छोड़ते, वैसे ही व्यायाम भी न छोड़ें। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित ऐज इंटर न्यूट्रिशन के संस्थापक अरविंद मांडोट ने आधुनिक फिटनेस ट्रेंड्स को जैन दर्शन से जोड़ते हुए कहा, आज जिसे हम डाइट, डिटॉक्स और डिसिप्लिन कह रहे हैं, वह सब हमारे जैन शास्त्रों में हजारों साल पहले बताया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वह फैशन बन गया है। उन्होंने उपवास को अनशन, सीमित आहार को उन्नोदरी, इंद्रिय संयम को प्रतिसंलीमता, व्यायाम को काया क्लेश और तैलीय पदार्थों के त्याग को रस परित्याग से जोड़ते

हुए समझाया कि यह केवल शरीर नहीं, आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया भी है। झ्रंसंयोजिका संगीता सियाल ने कार्यक्रमों के प्रायोजकों का परिचय दिया। इस मौके पर आयोजित पैनल चर्चा में मैराथन कोच दर्शन जैन, न्यूट्रिशन विशेषज्ञ अरविंद जैन, एशियन मेडलिस्ट खिलाड़ी रीथ अब्राहम और न्यूट्रिशनस्ट मोक्षा सोलंकी ने विभिन्न चरणों में अनेक विषयों पर चर्चा की। मुख्य प्रायोजक ऐज इंटर इज न्यूट्रिशन द्वारा शीर्ष पाँच विजेताओं सहित सभी 40 प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस मौके पर जीतो चैंप्टरों, अपेक्स व केकेजी जौन के अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे। लेडीज विंग की उप चेयरपर्सन लता बोहरा, कोषाध्यक्ष संगीता पारख, सहमंत्री साक्षी नाहर व चंद्रा जैन सहित अस्मिता चौहान, संगीता सियाल, अंगिका बाफना, नीतू गुलेच्छा, कविता मुथा, हेमा सोलंकी एवं रेखा जैन ने महीने भर चले इस कार्यक्रम की व्यवस्था संभाली। महासचिव निधि पालरचा ने समापन सत्र का संचालन किया। संयुक्त सचिव साक्षी नाहर ने धन्यवाद दिया।



जेवाईएस ने पुलिस आयुक्त को दिया महावीर जन्मकल्याणक महोत्सव का आमंत्रण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। स्थानीय जैन युवा संगठन(जेवाईएस) के सदस्यों ने शुक्रवार को बेंगलूरु के पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें 31 मार्च को फ्रीडम पार्क में आयोजित होने वाले भगवान महावीर स्वामी के जन्म

कल्याणक महोत्सव में अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया। संगठन के अध्यक्ष मुकेश सुराणा ने पुलिस आयुक्त को संगठन की विचारधारा, उद्देश्य और सामाजिक-धार्मिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उपाध्यक्ष रितेश पामेचा ने इस वर्ष आयोजित होने वाले महावीर जन्म कल्याणक कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की।

पुलिस एवं सुरक्षा व्यवस्था के चेयरमैन महावीर दक ने पुलिस आयुक्त से व्यवस्थाओं में सहयोग मांगा और उनको मिलने का समय देने के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर संगठन के पूर्व अध्यक्ष महावीर मुणोत, पूर्व कोषाध्यक्ष संतोष डूंगरवाल, आतिश धोका, पुलिस एवं सुरक्षा व्यवस्था समिति के सह चेयरमैन आशीष समदड़िया, रितेश धोका आदि उपस्थित थे।



यशवंतपुर में निशुल्क सर्वाइकल कैंसर जांच शिविर 4 को

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। अखिल भारतीय तैरापथ महिला मंडल के तत्वावधान में यशवंतपुर महिला मंडल द्वारा वर्ल्ड कैंसर डे पर निशुल्क सर्वाइकल कैंसर टेस्ट का आयोजन 4 फरवरी को किया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में कैंसर कैंप के बैनर का अनावरण मुख्य

अतिथियों व पदाधिकारियों ने किया। अध्यक्ष रेखा पितलिया ने सभी का स्वागत किया। पूर्व अध्यक्ष मीनाक्षी दक ने सभी को सर्वाइकल कैंसर के इस कैंप में अपनी जांच कराने की प्रेरणा दी। कर्नाटक कैंसर सोसायटी की सचिव डॉ. आर. नागरत्ना ने सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी दी। मुख्य अतिथि के रूप में कांठा प्रांत के अध्यक्ष गौतम मुथा व प्रायोजक महावीर

गन्ना आदि ने बैनर का अनावरण किया। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष पद्मा सुराणा, परिषद के अध्यक्ष धर्मेश डूंगरवाल, सभा के मंत्री अनिल दक, मंदिर संप्रदाय की अध्यक्ष फुलवाबाई नाहर, मुगावती मंडल की अध्यक्ष मीनाक्षी शृणुत आदि उपस्थित थीं। संयोजिका प्रीति मुथा ने शिविर की जानकारी दी। संचालन मंत्री टीना पितलिया ने किया। प्रिया डूंगरवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया।

उत्सव



दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु के मले महादेवर स्वामी सेवा ट्रस्ट, बापूजीनगर द्वारा आयोजित श्री मले महादेवर जात्रा उत्सव में मारुति मेडिकल के प्रमुख व समाजसेवी महेंद्र मुणोत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने महादेवर भगवान की पूजा कर जरूरतमंद बच्चों को शैक्षणिक सामग्री वितरित की। आयोजकों ने मुणोत का सम्मान किया।

आने वाले बजट से आम व्यक्ति की उम्मीदें और क्या कहता है इकोनॉमिक सर्वे-2026 ?



सीए. डॉ. सुनील शर्मा, मुम्बई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुम्बई। जैसे-जैसे बजट-2026 का दिन 1 फरवरी करीब आ रहा है, उम्मीदें केवल कॉर्पोरेट बोर्डरूम में ही नहीं, बल्कि भारत के हर घर में बढ़ रही हैं। उद्योगपतियों, व्यवसायियों, वेतनभोगी करदाताओं और घर खरीददारों से लेकर छोटे निवेशकों, पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों तक हर आम व्यक्ति यह उम्मीद कर रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन केंद्रीय बजट पेश करते समय राहत, सरलता और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेंगी।

संसद में आर्थिक सर्वे 29 जनवरी 2026 को पेश हो चुका है और अब पूरा

फोकस इस बात पर है कि सर्वे में खींची गई तस्वीर को वित्त मंत्री बजट में कितनी मजबूती या नई दिशा देती हैं। आर्थिक सर्वे ने एक तरफ जीडीपी ग्रोथ, महंगाई, रोजगार और राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर सरकार के प्रदर्शन और चुनौतियों का लेखा-जोखा रखा, तो दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च बढ़ाने के संकेत भी दिए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण-2026 के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2027 (वित्तीय वर्ष 26-27) में 6.8% से 7.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जिसे मजबूत माइक्रो फंडामेंटल्स और निरंतर विनियामक सुधारों से समर्थन मिल रहा है। सर्वेक्षण में यह भी संकेत दिया गया है कि वित्त वर्ष 2027 में 'कोर' और 'हेडलाइन' मुद्रास्फीति दरें पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी अधिक रह सकती हैं, हालांकि इसे चिंता का विषय नहीं माना गया है। राजकोषीय मोर्चे पर, नवंबर-2025 तक भारत का राजकोषीय घाटा बजटीय अनुमानों का 62.3% रहा है, और सरकार ने वित्त वर्ष-2026 तक इसे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.4% के तकथ तक लाने का संकल्प दोहराया है और ये आंकड़े देश के सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक स्थिरता को दर्शाते हैं।

जहां तक आम आदमी की उम्मीदों का सवाल है, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उस पर टैक्स का भार कम से कम पड़े फिर भी यदि हम आम आदमी एवं आम निवेशक के

दृष्टिकोण से देखें तो यदि बजट-2026 तस्वीर को निवेश पर टैक्स के बोझ को कम करता है और विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के बीच समानता लाता है, तो इससे निवेशकों और राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर सरकार के प्रदर्शन और चुनौतियों का लेखा-जोखा रखा, तो दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च बढ़ाने के संकेत भी दिए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण-2026 के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2027 (वित्तीय वर्ष 26-27) में 6.8% से 7.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जिसे मजबूत माइक्रो फंडामेंटल्स और निरंतर विनियामक सुधारों से समर्थन मिल रहा है। सर्वेक्षण में यह भी संकेत दिया गया है कि वित्त वर्ष 2027 में 'कोर' और 'हेडलाइन' मुद्रास्फीति दरें पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी अधिक रह सकती हैं, हालांकि इसे चिंता का विषय नहीं माना गया है। राजकोषीय मोर्चे पर, नवंबर-2025 तक भारत का राजकोषीय घाटा बजटीय अनुमानों का 62.3% रहा है, और सरकार ने वित्त वर्ष-2026 तक इसे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.4% के तकथ तक लाने का संकल्प दोहराया है और ये आंकड़े देश के सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक स्थिरता को दर्शाते हैं।

केंद्रीय बजट 2026-27 में आम आदमी एवं मध्यम वर्ग के लिए होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली धारा 24(ल) के तहत छूट की सीमा को 2 लाख रु से बढ़ाकर 5 लाख रु करने की प्रबल मांग है, ताकि बढ़ती ब्याज दरों और घर की कीमतों के बीच खरीदारों को राहत मिल सके। इसके साथ ही बेंगलूरु और पुणे जैसे उपरते शहरों को 'मेट्रो' की श्रेणी में शामिल करने और एचआरए छूट की सीमा बढ़ाने की उम्मीद भी है ताकि शहरी क्षेत्रों में बढ़ते किराये के बोझ को कम किया जा सके। ऐसा भी मानना

है कि यदि सरकार इस बजट में सभी करदाताओं के लिए एक 'कॉमन आईटीआर फॉर्म' और रियल-टाइम इनकम टैक्स रिफंड जैसी व्यवस्था लागू करती है, तो इससे न केवल टैक्स फाइलिंग सरल होगी बल्कि आम वेतनभोगियों के पास निवेश और खर्च के लिए अधिक नकदी उपलब्ध होगी, जिससे अर्थव्यवस्था में भी उपभोग को बढ़ावा मिलेगा। जन साधारण की उम्मीदें हैं कि आयकर की न्यूनतम सीमा को भी बढ़ाया जाएगा और न्यू टैक्स रेजीम को भी और अधिक आकर्षक बनाने के कुछ कदम वित्तमंत्री उठाएंगी। साथ ही यह भी उम्मीद है कि धारा 80-उ एवम 80-ऊ में मिलने वाली छूट, जिसकी सीमा लगभग पिछले 10-12 साल से स्थिर है, उसे भी बढ़ाकर न केवल करदाताओं को टैक्स में राहत दी जाएगी बल्कि इस से बचत बढ़ेगी एवं स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को भी लाभ पहुंचेगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए स्टैण्डर्ड डिडक्शन को भी बढ़ाया जाना चाहिए।

केंद्रीय बजट-2026 अब अपनी तैयारी के अंतिम चरण में है, जो आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए विकसित भारत की दिशा एवं गति तय करेगा, इसलिए आम आदमी की निगाहें न सिर्फ टैक्स रत्नबंध या फिर टैक्स से होने वाली बचत पर हैं, बल्कि वित्तीय एवं आर्थिक क्षेत्र में होने वाले सुधारों पर भी हैं, साथ ही बढ़ती महंगाई, अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिप्रेक्ष्य, बाजारों में अनिश्चितता के बीच प्रत्यक्ष एवम परोक्ष रूप से राहत की भी आकांक्षा रखता है।



समाजहित, धर्म, मानवसेवा के कार्य करने वालों की अनुमोदना होनी चाहिए : उपप्रवर्तकश्री नरेशमुनि

संतों ने रांका परिवार की सेवा भावना की सराहना की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के के बसवनगुड़ी वीवीपुसम स्थित महावीर जैन धर्मशाला में शुक्रवार को अशोक कुमार महेंद्र कुमार रांका के नूतन आवास उद्घाटन के मौके पर उपप्रवर्तक श्री नरेश मुनिजी, शालिभद्रमुनिजी, नवदीक्षित मुनि हार्दिक मुनिजी, साध्वीश्री सत्यप्रभाजी, सुप्रभाजी, डॉ प्रतिभाश्रीजी का मंगल पदार्पण हुआ। इस प्रसंग पर उपप्रवर्तक श्री नरेश मुनिजी ने रांका परिवार की गुरु भक्ति, सेवा समापन भावना की सराहना की। उन्होंने कहा कि जीवन का सचा सुख त्याग में है। कृपण की नहीं, दानी, त्यागी की महिमा गाई जाती है। कंजूस, कृपण को कोई याद नहीं करता है। मुनिश्री ने कहा कि जो भी समाज हित में, धर्म क्षेत्र में, अच्छे कार्य करते हैं और दान, सेवा, साधर्मिकों के जीवन को ऊंचा उठाने में पुण्यवानी से प्राप्त लक्ष्मी को सद्ब्रय्य करता है वह हमेशा अनुमोदनीय होता है। उन्होंने आगे कहा, भौतिक सुख की

तुलना आक के दूध एवं चूने से की व आध्यात्मिक सुख की तुलना क्रमशः गाय, भैंस के दूध से एवं मक्खन से करते हुए कहा कि दोनों में संज्ञा दूध की है लेकिन गुणधर्म अलग अलग है। भौतिक सुख क्षणिक है। समय,काल, परिस्थिति के अनुसार भौतिक सुख बदलता रहता है लेकिन आत्मा का आध्यात्मिक सुख हमेशा एक जैसा रहता है। मुनिश्री ने महेन्द्र-मीना रांका को उनके विवाह की 30वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को आजीवन शील व्रत के प्रत्याख्यान ग्रहण करवाए तथा युवा दम्पति को क्रमशः आदर्श सुश्रविक रत्न एवं आदर्श सुश्रविका रत्न की उपाधि से अलंकृत किया। इस अवसर पर श्री शालिभद्रमुनिजी, साध्वीश्री सुप्रभाजी, डॉ श्री प्रतिभाश्रीजी, तरुणशीलाजी, आर्याश्रीजी ने भी रांका परिवार की गुरु भक्ति को सराहते हुए सेवा के कार्यों में निरन्तर आगे बढ़ते रहने का आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम का संचालन आराधना केन्द्र के महामंत्री महावीर चंद मेहता ने किया। इस अवसर पर समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।



आत्मा की उन्नति और शांति का प्रतीक होता है ध्वज : साध्वीश्री भव्यगुणा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के एवेन्यू रोड स्थित श्री मुनिसुव्रत स्वामी राजेंद्र सूरिधर जैन गुरुमंदिर में ध्वजारोहण के प्रसंग पर शुक्रवार को साध्वीश्री भव्यगुणाजी ने कहा कि ध्वजारोहण एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसमें संस्कार के शिखर पर ध्वज चढ़ाया जाता है, जो आत्मा की उन्नति और शांति का प्रतीक होता है। साध्वी

शीतलगुणाजी ने कहा कि जैन धर्म में ध्वजारोहण एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जिसमें ध्वज को ऊंचा चढ़ाया जाता है, जो ज्ञान, शांति और विजय का प्रतीक होता है। प्रकाश हिराणी ने बताया कि आज आचार्यश्री जयंतसेन सूरिधरजी का पाटोत्सव दिवस है। संघ के अध्यक्ष भंवरलाल कटारिया ने गुरुदेव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। ओटमल जैन, राजेश गांधीमुथा, गौतमचंद जैन सहित महिला परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमाबाई गांधीमुथा ने

गुरुदेव के गुणों के बारे में बताया। झ्रध्यजारोहण कार्यक्रम का लाभ मनोहर्मल थानमल भंडारी परिवार, गुरुदेव राजेन्द्रसूरी की कायमी ध्वजा का लाभ पानीदेवी हरतीमल सोलंकी परिवार ने लिया। संघ की ओर से लाभार्थियों का सम्मान किया गया। संघ व ट्रस्ट मंडल के सदस्यों ने दीप प्रज्वलन कर गुरुदेव के चित्र पर मान्यार्पण किया। मुनिसुव्रत महिला मंडल ने सत्तरह भेदी पूजन पढ़ाई गई। प्रवीण गुरु ने विधि विधान कराया।



बसवनगुड़ी जिनकुशल दादावाड़ी में मुमुक्षुद्वय का हुआ सम्मान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के जिनकुशलसूरी जैन दादावाड़ी ट्रस्ट बसवनगुड़ी के तत्वावधान में शुक्रवार को मुनिश्री मलयप्रभसागरजी व मुकुलप्रभसागर जी की निश्रा में मुमुक्षु द्वय का सम्मान किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष तेजराज मालानी, पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र कुमार रांका, कोषाध्यक्ष रणजीत ललवानी, प्रवक्ता अरविन्द कोठारी, प्रकाश

भंसाली, पुखराज कयाड़, महिला परिषद की अध्यक्षा आरती जैन, पवनी बाफना ने दोनों मुमुक्षुओं को तिलक लगाकर, माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। महामंत्री कुशलराज गुलेच्छा ने शुभकामनाएं दी। झ्रङ्गट्रस्ट के ललित डाकलिया ने बताया कि सूरत निवासी मुमुक्षु जिनल मरडिया और हर्षिता देसाई की जैन भगवती दीक्षा सूरत में 14 मई को प्रतिष्ठाचार्य खरतर गच्छाधिपति आचार्यश्री जिन मणिप्रभसूरीधरजी और गच्छगणिनी साध्वी सुलोचनाश्रीजी की निश्रा में सम्पन्न

होगी। मुमुक्षुद्वय ने साध्वीश्री प्रियदर्शानिभाजी म. सा. के पास अध्ययन ग्रहण किया है। सम्मान समारोह में मलयप्रभसागरजी ने दोनों मुमुक्षुओं के संयम के प्रति दृढ़ भावना और संयम को भी जाना और उन्हें संयम जीवन पर आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी। दादावाड़ी ट्रस्ट की ओर से मुमुक्षुओं के माता और पिता का सम्मान किया गया। इस अवसर पर दादावाड़ी ट्रस्ट से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे।

कडलूर में बुजुर्ग किसान को पेट्रोल डालकर आग लगाई

कडलूर। तमिलनाडु के कडलूर जिले में आपसी रंजिश की वजह से 70 वर्षीय एक किसान को दो व्यक्तियों द्वारा कथित तौर पर पेट्रोल डालकर जलाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, पीड़ित किसान राजेंद्रन मालिगमपट्टु का रहने वाला है और फिलहाल अस्पताल में उसका उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि यह घटना 29 जनवरी की शाम करीब 6:50

बजे कदंपुलियूर गांव के पास उस समय हुई, जब राजेंद्रन एक दोपहिया वाहन पर पीछे बैठकर जा रहे थे। इस बीच, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कणम (अन्नाद्रमुक) के महासचिव एम्पपादी के. पलानीस्वामी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस घटना के वीडियो का हवाला देते हुए सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कणम (द्रमुक) सरकार की आलोचना की और राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए।